**Indian J. Soc & Pol. 03(02): 2016: 107-110** **ISSN 2348-0084 (P)**
**ISSN 2455-2127 (O)**

# नक्सलवाद और भारत की सुरक्षा

**आरती यादव**[1]
[1]शोधछात्रा, रक्षा अध्ययन विभाग, सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी, राजस्थान, भारत

**ABSTRACT**

***किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न उतना ही पुराना है जितना कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा से तात्पर्य राष्ट्र की क्षेत्रीय अखण्डता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था और मूल्यों को बरकरार रखना है। आज भारत अनेक बाह्य एवं आन्तरिक समस्याओं से जूझ रहा है, जिसका कारण न केवल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक है बल्कि भौगोलिक भी है। उक्त अनेक समस्याओं में से एक प्रमुख आन्तरिक समस्या ''नक्सलवाद'' है। नक्सलवाद भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरा है। नक्सलवाद एक ऐसी गम्भीर समस्या है जो अपने ही समाज के एक ऐसे वर्ग या समूह के द्वारा अपनी ही 'व्यवस्था' (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक) खिलाफ आक्रोश है, जो आर्थिक कारणों विशेष रूप से 'भूमि आवंटन' (जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों का लागू न होना) के साथ–साथ सामाजिक भेदभाव के कारण उत्पन्न हुई। किन्तु बात यहीं नहीं रूकती, यह आक्रोश इस कदर भड़का कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जिसको लेकर न केवल राज्य सरकारें बल्कि केन्द्र सरकार भी चिन्तित है। सरकारें भी इस समस्या से निजात दिलाने में सफल नहीं हो पा रही है। इसके पीछे जन समर्थन का अभाव प्रमुख कारण है।***

***KEYWORDS:*** *नक्सलवाद, माओवाद, सुरक्षा,*

आतंकवादी तरीकों का आश्रय लेना नक्सली आन्दोलन का एक अविभाज्य अंग बनता जा रहा है। किन्तु नक्सलवाद और आतंकवाद को एक नहीं माना जा सकता। आतंकवादियों से अलग नक्सलवादियों के मुख्य लक्ष्य तथा कथित ''शत्रु वर्ग'' (Class Enemies) होते हैं।(सिंह,पृ 396) नक्सली हिंसा केवल कानून–व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं समझी जानी चाहिए बल्कि इसका हल उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निदान में निहित है। नीति बनाने और लागू करने वालों को यह समझना चाहिए कि नक्सली तब तक आंतरिक अशांति पैदा करते रहेंगें जब तक उनकी आर्थिक समस्याएं निपटाई नहीं जाएगी।(विवेक, पृ 633)

नक्सलवादी मुख्य रूप से देश के 9 राज्यों के 76 जिलों में विस्तृत है। ये नक्सलवादी राज्य है– आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।(विवास वार्षिकी 2015 पृ 19)

वर्ष 2009 तक नक्सलवादी देश के 20 राज्य के लगभग 220 जिलों में सक्रिय थे। देश के लगभग 40% भाग में नक्सलवादी फैल चुके है। नक्सलियों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्र को 'लाल गलियारा' (Red Corridor) कहते हैं।(वही)

भारतीय सुरक्षा विभाग के अनुसार वर्तमान में लगभग 20,000 आर्म्ड कैडर नक्सलवादी संगठन के लिए काम कर रहे है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है। लगभग 40 हजार वर्ग कि0मी0 में फैले बस्तर क्षेत्र में नक्सलवादियों का अधिक प्रभाव है। विचारथ और रणनीति के आपसी मतभेदों के चलते नक्सलवादियों में अनेक गुट बने, लेकिन 21 सितम्बर 2004 को 'पीपुल्स वॉर ग्रुप' और भारती माओवादी कम्यूनिस्ट सेन्टर ने आपसी समन्वय से 'कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवाद) का गठन किया भूमिगत रहकर सी.पी.आई. (माओवादी) ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए हथियारबंद नक्सलवादी गिरोहों को मजबूत किया। इन्होंने 'नक्सलाइट माओवाद की विद्रोही सेना बनाई। भारतीय संविधान को नकारते हुए नक्सलवादी भारत की पूरी राजनीतिक व न्याय व्यवस्था को साम्राज्यवाद और सामंतवाद की कठपुतली मानते हैं। और भारत के लोकतंत्र को छदम लोकतंत्र कहते हैं। वे नेपाल से बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश तक एक 'संघन लाल गलियारा बनाने में प्रयासरत है। वर्ष 2009 में नक्सलवाद की समस्या के एक विकराल स्वरूप का सामना हुआ जब माओवादियों ने पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ी। माओवादी नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चिंतलनार में अब तक के सबसे बड़े नक्सली हमले को अंजाम देते हुए 6 अप्रैल 2010 को CRPF के 75 जवानों की मार डाला। इस घटना ने नक्सलियों के क्रूरतम चेहरे को बेनकाब किया। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने पहली बार किसी राजनीतिक कार्यालय पर रणनीति के साथ हमला किया।(वही) वर्ष 2010 में 998 सुरक्षा कर्मी एवं नागरिकों की हत्या ने 2010 के वर्ष को अब तक सबसे हिंसक बना दिया। यह सिलसिला 2011 में भी जारी रहा। नक्सलियों ने 16 फरवरी 2011 की उड़ीसा के मलकानगिरि के कलेक्टर आर0 विनीत कृष्ण और जूनियर इंजीनियर पवित्रा मांझी को अगवा कर लिया तथा इनकी रिहाई हेतु अनगिनत माँगे रखी, जिनमें नक्सली नेता प्रसादम और

*1: Corresponding Author*

श्रीनिवासुलू सहित 700 माओवादियों की रिहाई की शर्तें भी थी।(सिंह, पृ 07) उन्होंने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन कार्यक्रम को निशाना बनाया प्रमुख कांग्रेस नेताओं सहित 28 लोगों की हत्या कर दी। नक्सलवादियों ने महेन्द्र कर्मा नंदकुमार पटेल जैसे नेताओं की हत्या के बाद जिम्मेदारी लेते हुए बयान जारी किया कि– 'वे ऐसे नेतृत्व को समाप्त कर देंगे जो उनके विरूद्ध रणनीति तैयार करता है।'

नक्सलवाद के जन्म से अब तक के पूरे इस सशस्त्र विद्रोह को 3 दौर में विभाजित किया जा सकता है–

(i) प्रथम दौर (1967–2005) ग्रामीणों को दिवास्वप्न दिखाकर भड़काना।

(ii) दूसरा दौर (2005–2013) – सुरक्षाकर्मियों की हत्या व अधिकारियों का अपहरण।

(iii) तीसरा दौरा (2013 से शुरू)– सीधे राजनीतिक हस्तियों की हत्या।(विवास वार्षिकी,2015 पृ 19)

## नक्सलवाद के कारण

नक्सलवादी आन्दोलन का प्रारम्भ पिछड़ेपन व अविकसित स्थिति के कारण हुआ था। हमारी योजनाएं कागज पर कितनी ही अच्छी बनी हों। परन्तु इनके क्रियान्वयन में बहुत कमी रही है। योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया कि स्वतंत्रता के 60 वर्ष पश्चात् भी हमारी 1/4 आबादी आज भी गरीब है। विकास हुआ, जी0डी0पी0 बढ़ी है, परन्तु विकास का लाभ सभी वर्गों को आवश्यकतानुसार नहीं मिला है। जनजातियों के साथ विशेष तौर पर सौतेला व्यवहार हुआ हे। एक आकलन के अनुसार 1947 से 2004 के बीच विभिन्न योजनाओं के कारण देश में कुल 6 करोड़ से ज्यादा आदमी विस्थापित हुए हैं। इनमें 40% से ज्यादा जनजातीय लोग थे। भूमि सम्बन्धी सुधार जो होने चाहिए थे वे आंशिक रूप से ही हुए हैं। राज्य सरकारें इस दिशा में उदासीन हैं।(दयाल व सिंह, पृ 54)

भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि विकास योजनाएं कागज पर ही धरी रह जाती हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटक अहलूवालिया के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार जो खर्च करती है उसमें 1 रूपए का केवल 16 पैसा ही गरीब तक पहुँच पाता है। फलस्वरूप जो लाभ गरीब तबके तक पहुँचना चाहिए वह नहीं पहुँच पाता।(वही)

## नक्सलियों के बदलते चेहरे और उनसे निपटने में सरकार से हुई कुछ गलतियाँ

1. शुरूआती नक्सलबाड़ी विद्रोह को वर्ग संघर्ष मानकर छोड़ देना।
2. 1970 के दशक में नक्सलियों के बीच उभरी गुटबाजी के बावजूद सुरक्षा बलों को उन्हें समाप्त करने की अनुमति नहीं देना।
3. अप्रैल 1980 में कोंडापल्ली सीतारमैया द्वारा आन्ध्र प्रदेश में सक्रिय पाँच गुटों में एकता स्थापित कर गठित किए गए पीपुल वार ग्रुप (PWG) के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करना।
4. 1982 में तेलगूदेशम पार्टी नेता एन0टी0 रामाराव द्वारा नक्सलियों को सच्चा देशभक्त बताना और पुलिस को माओवादियों के विरूद्ध कार्यवाही करने से मना करना।
5. 1989 में कांग्रेस के एम0 चेन्ना रेड्डी द्वारा एन0टी0 रामाराव को हराने के लिए चुनाव में खुलकर नक्सलियों से समर्थन माँगना और मुख्यमंत्री बनने पर नक्सलियों की हैदराबाद में बड़ी रैली आयोजित करने देना।
6. विभिन्न जाँच रिपोर्टों पर कार्यवाही न करना।
7. 2010 में 76 सी0आर0पी0एफ0 जवानों की हत्या के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेना–वायुसेना तैनात करने का फैसला होने से पूर्व ही वायुसेना का विरोध करना।
8. पंजाब से आतंकवाद समाप्त करने वाले डीजीपी के0पी0एस0 गिल का 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार का सलाहकार बनाने के बावजूद उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य न करने देना।
9. कैग (CAG) के अनुसार 2000 से 2009 के बीच सरकार द्वारा राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 8900 करोड़ रूपये दिये गए लेकिन राज्य सरकारें केवल 690 करोड़ खर्च किये।(विवास वार्षिकी, 2015 पृ 19)

## सरकार द्वारा किये गये प्रयास

इस दिशा में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से पहले सभी बड़ी समस्या यह है कि प्रान्तों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना संविधान के आधार पर प्रान्तों का दायित्व है और केन्द्र सरकार इसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकती दूसरे विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की सरकार होने से आपसी समन्वय भी एक प्रमुख समस्या रही है, क्योंकि एक राज्य में दबाव पड़ने पर माओवादी दूसरे राज्य में प्रयाण कर जाते हैं तथा वहां से अपनी गतिविधियां संचालित करने लगते हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया कि माओवादियों के विरूद्ध अभियान की कमान राज्य सरकार ही सम्भालेगी तथा केन्द्रीय सुरक्षा बल सहायता का काम करेंगे। महाराष्ट्र में विशेष सचिव श्री कुमावत के नेतृत्व में अन्तःमंत्रीय समूह का गठन किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अब संरचनात्मक विकास के 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। अर्द्धसैनिक बलों की 33 बटालियन को नक्सल प्रभावित प्रान्तों में भेजा गया है,

साथ ही 70 अतिरिक्त बटालियन एवं 9 ग्रेहाउण्डस बटालियन को डी0जी0पी0 (सी0आर0पी0एफ0) कोडे दुर्गा प्रसाद के अधीन रखा गया है। सरकार द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के लिए 73,000 करोड़ के अतिरिक्त धन की भी व्यवस्था की है जिससे इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा सके। सरकार का मूल प्रयत्न इस बात से है कि अगले एक दो वर्षों को गति दी जा सके। सरकार का मूल प्रयत्न इस बात से है कि अगले एक दो वर्षों में नक्सलवादी तंत्र को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। इसी को ध्यान में रखकर यह भी व्यवस्था हो जाता है तो उसे 2500 रूपये प्रतिमाह सहायता प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही माओवादियों का सामना करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने हेतु छत्तीसगढ़ के कांकेर में 'काउंटर टेररिज्म एवं जंगल वार फेयर कालेज' में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गयी है।(शर्मा, पृ 84)

## सुझाव

1. नक्सलवाद के सामाजिक–आर्थिक कारणों से निपटने की कुंजी सुशासन और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में निहित है।
2. केन्द्र सरकार नक्सली हिंसा को कानून–व्यवस्था की समस्या मानती है इसे सामाजिक–आर्थिक समस्या के रूप में भी सुलझाने की जरूरत है।
3. नक्सली खतरे से राजनीतिक सुरक्षा एवं विकास तथा लोक अवधारणा प्रवर्धन के मोर्चों पर एक साथ समग्र रूप से निबटना चाहिए।
4. जब तक नक्सलवादी हिंसा एवं शस्त्रों का परित्याग करने के लिए सहमत नहीं होते तब तक प्रभावित राज्यों द्वारा उनसे किसी भी प्रकार की शान्ति वार्ता नहीं की जानी चाहिए।
5. राजनीतिक दलों को नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि वहां की युवा पीढ़ी को नक्सलवादी विचारधारा के रास्ते से हटाया जा सके।
6. जहां नक्सलवादी गतिविधियां अथवा प्रभाव की सूचना है, परन्तु नक्सलवादी हिंसा की नहीं, वहवां एक पृथक दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें पिछड़े इलाकों के त्वरित सामाजिक–आर्थिक विकास तथा गैर–सरकारी संगठनों, बुद्धिजीवी वर्ग, नागरिक स्वतंत्रता समूहों इत्यादि के साथ नियमित सम्पर्क बनाये रखने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना होगा ताकि नक्सलवादी विचारधारा तथा गतिविधियों को मिलने वाले खुले समर्थन को कम किया जा सके।
7. नक्सलवादियों के विरूद्ध स्वैच्छिक स्थानीय प्रतिरोधी समूहों को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखे जाने चाहिए।
8. नक्सलवादी विचारधारा तथा हिंसा की निरर्थकता एवं इससे होने वाली जीवन एवं सम्पत्ति की क्षति को तथा प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की विकास योजनाओं का प्रचार करने के लिए मीडिया का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सरकारी तंत्र में लोगों की आस्था एवं विश्वास को बहाल किया जा सके।
9. भूमि सुधारों के त्वरित कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में भूमिहीन निर्धन लोगों को भूमि वितरित करने और सड़क, संचार, विद्युत आदि जैसी भौतिक अवस्थापना का विकास सुनिश्चित करने एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
10. नक्सली भय के कारण जो ठेकेदार व कर्मी विकास कार्य करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किये जाने की आवश्यकता है।
11. केन्द्र सरकार को सुरक्षा तथा विकास दोनों मोर्चों पर प्रभावित राज्यों के प्रयासों एवं संसाधनों में सहयोग करना जारी रखना होगा तथा इस अवस्था से सफलतापूर्वक निबटने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा।

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि राज्यों को सुरक्षा बलों की प्रशिक्षित ईकाइयां तैयार करने के लिए जो धन केन्द्र सरकार ने खर्च करने का आश्वासन दिया है उसे विशेष पैकेज के रूप में तत्काल राज्यों को सौंप दिया जाय और इस धन का ये राज्य सरकारें परिवहन तथा संचार व्यवस्था सुधारने तथा शिक्षा की सुविधायें बढ़ाने तथा बेरोजगारी खत्म करने पर खर्च करें, क्योंकि विकास कार्यों की कमी के कारण ही नक्सलवाद को पनपने में सहायता मिल रही है। राज्य सरकारें भरपूर विकास कार्य करें और केन्द्रीय सुरक्षा बल इनके विरूद्ध जोरदार कार्यवाही करें तभी इस समस्या से निजाद मिल सकती है।

शोषण और भ्रष्टाचार में लिप्त हमारी पतित व्यवस्थाओं के विरोधस्वरूप उत्पन्न विद्रोहपूर्ण विचारधारा से प्रारम्भ होकर एक जन–आन्दोलन के रूप में विकसित होते हुए आतंक के पयार्य बने नक्सलवाद ने बंगाल से लेकर सम्पूर्ण भारत में आज अपने पैर पसार लिए है। इस लम्बी यात्रा के बीच इस विद्रोह के जनक कानू सान्याल ने विकृतावस्था को प्राप्त हुई अपनी विचारधारा के हश्र से निराश होकर आत्महत्या भी कर ली। यह कटु सत्य है कि भ्रष्ट व्यवस्था और पतित नैतिक मूल्यों के प्रतिकार से अस्तित्व में आए नक्सलवाद को आज भी वास्तविक पोषण हमारी व्यवस्था द्वारा ही मिल रहा है।

सरकार नक्सल समस्या को गंभीर चिन्ता के विषय के रूप में देख रही है। केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें समस्या के निदान के लिए प्रतिबद्ध एवं सुनिश्चित है। नक्सल समस्या को हल करने की हमारी रणनीति के दो आयाम होने चाहिए। पहला– हमें एक प्रभावी पुलिस प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, दूसरा– हमें प्रभावित आदिवासियों की विचारधाराओं व दिमागों से अलगाव व वंचना की भावना को कम करने पर केन्द्रित होना चाहिए।

निश्चित ही अब समय आ गया है कि नक्सलवादियों को समाप्त करने के बजाए नक्सलवाद के मूल कारणों को समाप्त किया जाए। अपने ही लोगों (नक्सलियों) पर सेना का प्रयोग किसी भी समझदार दिमाग से एक हल नही है। नक्सल समस्या को एक आन्तरिक अशांति के रूप में देखा जाना चाहिए न कि किसी विदेशी शत्रु द्वारा सशस्त्र विद्रोह के रूप में। मूलतः सरकार को नक्सलियों द्वारा फैलाए नकारात्मक प्रचार को काटने के लिए केवल प्रभावी विकासात्मक प्रक्रिया जारी रखना चाहिए। केन्द्र सरकार को नक्सलवाद द्वारा उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा व विकासात्मक मोर्चों पर राज्य सरकारों के संसाधनों व प्रयासों का समन्वय व अनुपूरण जारी रखना चाहिए।

**सन्दर्भ**

सिंह, डॉ0 अशोक कुमार : *आधुनिक स्त्रातजिक विचारधारा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा,* बरेली, प्रकाश बुक डिपो

विवेक एस0 राज, 2015 : *समकालीन भारतीय मुद्दे,* नई दिल्ली, सिविल सर्विसेज टाइम

विवास वार्षिकी, 2015,

सिंह, राजेश कुमार : *नक्सलवाद और पुलिस की भूमिका,*

दयाल, डॉ0 जे0 और शिवराज सिंह, : *नक्सलवाद : सुरक्षा चुनौती या अमन का सवाल,*

शर्मा, डॉ0 श्याम बहादुर : *नक्सलवाद, भारतीय अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह*